

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक रिट याचिका संख्या 1731/2024

नीरज पुरबिया पुत्र श्री प्रेम चंद पुरबिया, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी 263, सहेली नगर उदयपुर, वर्तमान में 154 बिल्डिंग, साल्मिया, कुवैत.

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर के माध्यम से.
2. प्रमुख सचिव, गृह सचिवालय, जयपुर.
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर.
4. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर.
5. श्री जितेंद्र आंचलिया जैन पुत्र भेरूलाल जैन, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी 73 हिरण मगरी सेक्टर संख्या 4, उदयपुर, राज.
6. श्री कैलाश सिंह संधू, पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़.
7. श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल, पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर.
8. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली.

-----प्रतिवादीगण

संबंधित के साथ

एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 1279/2023

1. लवलीना पत्नी स्वर्गीय श्री नीलेश पुरबिया, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी 263, सहेली नगर, उदयपुर.
2. अंकित मेवाड़ा पुत्र श्याम लाल मेवाड़ा, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी सरदारगढ़, तहसील आमेत, जिला राजसमंद.

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से.
2. नीरज पुरबिया पुत्र प्रेम चंद पुरबिया, निवासी प्लॉट संख्या 262/20, सहेली नगर, उदयपुर.

-----प्रतिवादीगण

एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 2526/2023

निखिल पोरवाल पुत्र बसंत पोरवाल, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी 3-बीआईआई, हजारेश्वर कॉलोनी, उदयपुर.

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से.
2. नीरज पुरबिया पुत्र प्रेम चंद पुरबिया, निवासी प्लॉट संख्या 262/20, सहेली नगर, उदयपुर.

-----प्रतिवादीगण

एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 3387/2023

जितेंद्र पुत्र श्री भेरूलाल, आयु लगभग 50 वर्ष, जाति जैन, निवासी 73 हिरण मगरी सेक्टर संख्या 4 उदयपुर, राज.

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से.
2. नीरज पुत्र श्री प्रेमचंद, जाति पुरबिया, निवासी 263/20 सहेली नगर पुलिस थाना सुखेर उदयपुर, राज.

-----प्रतिवादीगण

एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 5259/2023

राजेश कोठारी पुत्र श्री प्रकाश चंद, आयु लगभग 40 वर्ष, 190, लाल बाजार, नाथद्वारा, जिला राजसमंद.

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से.
2. नीरज पुरबिया पुत्र प्रेम चंद पुरबिया, प्लॉट संख्या 262/20, सहेली नगर, उदयपुर.

-----प्रतिवादीगण

एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 905/2024

मनोज श्रीमाली पुत्र जगनेश्वर सिंह माली, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 113, टेक्नोक्रेट सोसाइटी, बेदला रोड, पुलिस थाना अम्बामाता, जिला उदयपुर.

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से.
2. नीरज पुत्र श्री प्रेमचंद, जाति पुरबिया, निवासी 263/20, सहेली नगर, पुलिस थाना सुखेर, उदयपुर (राज.).

-----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री ऋषभ हांडा, श्री वी. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री हर्षवर्धन सिंह राठौड़, श्री राजेश जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री विवेक श्रीमाली, सुश्री कामिनी जोशी, श्री डूंगर दान चारण, श्री एम.एस. राजपुरोहित, श्री दीपक मनारिया, श्री संजय माथुर.
प्रतिवादी (गण) की ओर से	:	श्री एन.के. गुर्जर, राजकीय अधिवक्ता-सह- अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ श्री योगेंद्र चारण, श्री हरिशचंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप महानिरीक्षक कार्यालय, उदयपुर, डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा, महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर.

माननीय श्री न्यायमूर्ति फरजंद अली

आदेशरिपोर्ट किए जाने योग्य20/02/2025आपराधिक रिट याचिका संख्या 1731/2024

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह तात्कालिक याचिका दायर करके, उदयपुर के एक स्थायी निवासी याचिकाकर्ता ने पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र आचलिया और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए अवैध और मनमाने कृत्यों, जिसमें 1.83 करोड़ रुपये की राशि की जबरन वसूली शामिल है, के निवारण के लिए इस न्यायालय से राहत मांगी है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि अभियुक्तों के कृत्यों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 300 ए के तहत गारंटीकृत कई मौलिक अधिकारों का

उल्लंघन किया है. इसके अलावा, याचिकाकर्ता जांच के लिए और इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जैसी निष्पक्ष एजेंसी को हस्तांतरित करने के लिए उचित निर्देश चाहता है, यह तर्क देते हुए कि राज्य पुलिस और अन्य अधिकारी एक निष्पक्ष और पक्षपातरहित जांच सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं, जिससे अभियुक्तों को जवाबदेही से बचाया जा रहा है.

2. याचिकाकर्ता, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर, 1993 से कुवैत में रह रहा है, जहाँ उसने एक सफल व्यवसाय, पेगासस टर्न सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड स्थापित किया है, जो कुवैत, दुबई और भारत में संचालित होता है. याचिकाकर्ता तब से भारत में अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए पैसे भेज रहा है. 2007 में, याचिकाकर्ता ने भारत में संपत्ति खरीदने के लिए अपने भाई नीलेश पुरबिया को धन हस्तांतरित किया, लेकिन उसके भाई ने आर्थिक रूप से योगदान किए बिना धोखाधड़ी से खरीद विलेख में अपना नाम भी डाल दिया. 06.11.2019 को अपने भाई की असामयिक मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता से 13.02.2022 को उसकी भाभी लवलीना ने संपर्क किया कि वह संपत्ति को पाँच करोड़ रुपये में बेच दे और उसके लिए नई संपत्ति खरीद दे. हालाँकि, लवलीना ने पुलिस के साथ मिलीभगत करके एक ऐसा परिदृश्य बनाया जिसके कारण याचिकाकर्ता को 17.02.2022 को मनगढ़ंत आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 380 और 120 बी के तहत एक बाद की प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसका याचिकाकर्ता कड़ाई से खंडन करता है.
3. 18.02.2022 को, उप-निरीक्षक रोशनलाल और अन्य के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने याचिकाकर्ता के कार्यालय का दौरा किया और एक लेखाकार और एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया, जिससे याचिकाकर्ता को मामले में और फंसाया गया. याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उदयपुर के कार्यालय से संपर्क किया, जहाँ उसे सूचित किया गया कि पुलिस को संपत्ति विवाद में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही लागू होगी. हालाँकि, याचिकाकर्ता को बाद में पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र आचलिया और उनके सहयोगियों द्वारा दबाव में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, उसे इनकार करने पर जेल भेजने और उसके पासपोर्ट को जब्त करने की धमकी दी गई. याचिकाकर्ता, गलत निरोध के डर से, मनगढ़ंत प्राथमिकियों

को वापस लेने और अपनी संपत्ति का नियंत्रण वापस पाने के लिए समय के साथ 1.83 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए विवश हुआ. घटनाओं के पूरे क्रम को हस्तलिखित समझौतों, वीडियो फुटेज और प्रेषण रसीदों के माध्यम से दस्तावेजित किया गया था. हालांकि, स्थिति तब और खराब हो गई जब याचिकाकर्ता को अभियुक्तों द्वारा लगातार धमकी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसमें मामले को सुलझाने के लिए अतिरिक्त रकम की मांग भी शामिल थी.

4. याचिकाकर्ता का दावा है कि पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र आंचलिया और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए कृत्यों, जिनमें धमकियां, जबरन वसूली और गलत कारावास शामिल हैं, संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन हैं. याचिकाकर्ता इस बात पर प्रकाश डालता है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज करने और बाद में आरोप पत्र दाखिल करने के बावजूद, एसीबी अधिकारियों और कार्मिक विभाग (डीओपी) सहित राज्य प्राधिकरण अभियुक्तों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहे हैं, जिससे उन्हें दण्ड से मुक्ति के साथ काम करने की अनुमति मिल रही है. याचिकाकर्ता आगे बताता है कि पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र आंचलिया के निलंबन पर अवैध रूप से रोक लगा दी गई थी, और अभियुक्त को गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद बहाल कर दिया गया है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह राज्य तंत्र द्वारा अभियुक्तों को उनके कृत्यों के परिणामों से बचाने का एक प्रयास है, जिससे न्याय में बाधा उत्पन्न हो रही है.

5. इसके अलावा, याचिकाकर्ता का दावा है कि जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के मामले की जांच पक्षपाती अधिकारियों की संलिप्तता से दूषित हो गई है. अभियुक्त की जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के कई मामलों में संलिप्तता के स्पष्ट सबूतों के बावजूद, जांच को अभियुक्तों से ज्ञात संबंध रखने वाले अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया गया है, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक कैलाश सिंह संधू भी शामिल हैं, जिन्होंने पहले 2016 में आंचलिया को क्लीन चिट दी थी. याचिकाकर्ता का दृढ़ विश्वास है कि यह चल रही पुनः जांच कार्यवाही को पलटने और अभियुक्त को कानूनी नतीजों से बचाने के प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, याचिकाकर्ता अनुरोध करता है कि यह न्यायालय राज्य तंत्र के भीतर प्रणालीगत भ्रष्टाचार का संज्ञान ले और एक निष्पक्ष और पक्षपातरहित जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले

को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को हस्तांतरित करे.

6. याचिकाकर्ता आगे तर्क देता है कि प्रतिवादी प्राधिकरणों के कार्य, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र आचलिया के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने में देरी शामिल है, भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन स्वीकृति समय पर देने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का सीधा उल्लंघन है. याचिकाकर्ता का दावा है कि लगातार देरी और जांच को एक पक्षपाती अधिकारी को सौंपना कानूनी प्रक्रिया को पटरी से उतारने और अभियुक्त को मुकदमे का सामना करने से बचाने के जानबूझकर प्रयास हैं. इसलिए, याचिकाकर्ता इस न्यायालय से हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रार्थना करता है कि जांच और मुकदमा कानून के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़े.
 7. पक्षकारों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की जाँच की गई.
 8. जांच की निष्पक्षता के संबंध में याचिकाकर्ता की आशंका को स्वीकार किया जाता है; हालाँकि, यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि मामले की बार-बार उच्च पद वाले अधिकारियों द्वारा जाँच की गई है. अभिलेख दर्शाता है कि जांच विभिन्न पदानुक्रमित स्तरों पर कई स्तरों की छानबीन से गुजरी है, जिससे मनमानी या प्रक्रियात्मक अनियमितता के किसी भी प्रथम दृष्टया संदेह को समाप्त कर दिया गया है. इस न्यायालय ने पहली और दूसरी दोनों जांचों में शामिल जांच अधिकारियों के प्रतिवेदनों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया है, विशेष रूप से उनके विचारों में अंतर पर ध्यान दिया है. मामले की गंभीरता को पहचानते हुए, इस न्यायालय ने पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के अपने प्रयास में, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक (डीजी-एसीबी) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने का निर्देश दिया. सत्र के दौरान, डीजी-एसीबी को इस न्यायालय द्वारा जांच की ईमानदारी और कार्यप्रणाली के बारे में किसी भी लंबित संदेह को दूर करने के लिए सीधे प्रश्नों के अधीन किया गया. न्यायालय ने आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ उनकी प्रतिक्रियाओं की सावधानीपूर्वक जाँच की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई प्रक्रियात्मक चूक या जांच विसंगतियाँ मौजूद हैं या नहीं.
-

9. एक व्यापक मूल्यांकन के बाद, यह न्यायालय आश्वस्त है कि जांच के सभी पहलुओं को संबंधित एजेंसी द्वारा पूरी तरह से संबोधित किया गया है, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची है. डीजी-एसीबी और उनकी टीम द्वारा किए गए विस्तृत पुनरवलोकन से यह निष्कर्ष और मजबूत होता है कि उचित प्रक्रिया का तत्परतापूर्वक पालन किया गया है. जांच के प्रारंभिक चरणों में नोट की गई विसंगतियों को एक तार्किक और कानूनी रूप से सुदृढ़ तर्क के साथ विधिवत मिलाया गया था, और कोई स्पष्ट त्रुटि, प्रक्रियात्मक दुर्बलता या दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं पाया गया है जिससे कि न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े.
10. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) राज्य पुलिस के तहत संचालित एक विशेष जांच अभिकरण है, जिसे लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों की जांच करने के लिए आवश्यक कानूनी अधिकार और विशेषज्ञता प्राप्त है. विचाराधीन मामले को एसीबी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में कड़ी जांच के अधीन किया गया है. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जांच निष्कर्ष, जांच अधिकारियों की ओर से अंतर्निहित पूर्वाग्रह या दुर्भावना की धारणा को वारंट करने वाली कोई अनियमितता नहीं दर्शाते हैं. जांच के परिणामों से मात्र असंतोष जांच को दूसरी अभिकरण को हस्तांतरित करने की मांग करने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार प्रदान नहीं करता है. जांच प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप बाध्यकारी कारणों और पूर्वाग्रह या न्याय की विफलता के स्पष्ट संकेतों पर आधारित होना चाहिए, जो वर्तमान मामले में अनुपस्थित हैं. बार-बार हस्तांतरण नियमित कानूनी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को कमजोर करेगा और जांच हस्तांतरण शक्तियों के प्रयोग को उचित ठहराने वाली असाधारण परिस्थितियों के महत्व को कम कर देगा.
11. राज्य पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच के हस्तांतरण से संबंधित न्यायशास्त्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से स्थापित किया गया है. न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में जांच को हस्तांतरित करने के लिए अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर सकता है:

1. जब राज्य प्राधिकरणों के उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हों;

2. जब आरोप स्वयं जांच एजेंसी के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित हो; या
 3. जब जांच प्रथम दृष्टया दूषित या पक्षपाती पाई जाए.
12. हालाँकि, वर्तमान मामले में, इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है. रिकॉर्ड पर ऐसा कोई पुष्ट साक्ष्य मौजूद नहीं है जो यह सुझाव दे सके कि उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इस तरह से जांच को प्रभावित किया है जिससे इसकी ईमानदारी से समझौता हो. इसके अलावा, पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र आंचलिया और अन्य के खिलाफ आरोपों की पहले ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की जा चुकी है, और जहाँ आवश्यक हो, उचित कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है. यह तर्क कि जांच पूर्वाग्रह के साथ आयोजित की गई है, किसी भी भौतिक प्रमाण से अपुष्ट रहता है जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को आवश्यक बना सके.
13. इस न्यायालय ने, जांच की प्रक्षेपवक्र की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद, पक्षपात, अनुचित प्रभाव या भौतिक तथ्यों के जानबूझकर दमन के कोई प्रदर्शनकारी संकेत नहीं पाए हैं. याचिकाकर्ता के इस तर्क में कि जांच प्रक्रिया में हेरफेर किया गया है, साक्ष्य समर्थन की कमी है. अन्याय की धारणा मात्र न्यायिक हस्तक्षेप का आधार नहीं बन सकती जब तक कि न्याय की स्पष्ट विफलता को इंगित करने वाले ठोस प्रमाण द्वारा इसकी पुष्टि न हो. चूंकि ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए जांच को हस्तांतरित करने की प्रार्थना अयोग्यतापूर्ण है.
14. उपरोक्त विचारों को देखते हुए, यह न्यायालय चल रही जांच में हस्तक्षेप करने या मामले को सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र अभिकरण को हस्तांतरित करने का कोई बाध्यकारी आधार नहीं पाता है. याचिकाकर्ता की शिकायतें, हालांकि गंभीर हैं, कानून के ढांचे के भीतर नामित प्राधिकरणों द्वारा विधिवत संबोधित की गई हैं. न्यायिक हस्तक्षेप की वारंटी देने वाली न्याय की कोई प्रदर्शनकारी विफलता या प्रक्रियात्मक दुर्बलता नहीं है.
15. तदनुसार, यह याचिका योग्यता से रहित होने के कारण खारिज की जाती है.
16. स्थगन याचिका का निपटारा किया जाता है.
-

**आपराधिक विविध याचिका संख्या 1279/2023 (लवलीना),
2526/2023 (निखिल पोरवाल), 5259/2023 (राजेश कोठारी)**

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत ये तात्कालिक याचिकाएं दायर करके, याचिकाकर्ता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 7 ए, और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत अपराधों के लिए 30.12.2022 को पुलिस स्टेशन भ्रष्टाचार निरोधक (विशेष इकाई), जयपुर में दर्ज प्राथमिकी संख्या 507/2022 को, साथ ही उससे उत्पन्न होने वाली सभी आनुषंगिक कार्यवाहियों को रद्द करने की मांग करते हैं.
2. याचिकाकर्ता, नीरज पुरबिया, का अपने मृत भाई की पत्नी, लवलीना पुरबिया, के साथ संपत्ति विवाद था, जिसके कारण लवलीना द्वारा 18.02.2022 को पुलिस स्टेशन सुखेर में प्राथमिकी संख्या 91/2022 दर्ज की गई थी. पार्टियों के बीच समझौते के बाद, 16.11.2022 को अदालत में एक अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई थी. इस बीच, नीरज पुरबिया ने 07.11.2022 को एसीबी मुख्यालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप 30.12.2022 को उप-निरीक्षक रोशन लाल के खिलाफ एसीबी मामला संख्या 507/2022 दर्ज किया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह द्वारा की गई जांच में रोशन लाल, पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र कुमार आंचलिया, और निजी व्यक्तियों मनोज श्रीमाली और रमेश राठौर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में यथासंशोधित) की धारा 7, 7 ए, 12 और भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 120 बी के तहत प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए गए. हालाँकि, लवलीना पुरबिया, अंकित मेवाड़ा, निखिल पोरवाल और राजेश कोठारी के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच लंबित रखी गई थी क्योंकि इस न्यायालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश दिया गया था.
3. पक्षकारों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की जाँच की गई.
4. मामले के अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि लवलीना पुरबिया, अंकित मेवाड़ा, निखिल पोरवाल और राजेश कोठारी सहित कुछ व्यक्तियों के खिलाफ

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत जांच को अंतरिम आदेश के कारण उनकी गिरफ्तारी को रोकने या संभवतः आगे के साक्ष्य की कमी के कारण लंबित रखा गया था. विशेष रूप से, मामला याचिकाकर्ता, नीरज पुरबिया, और उसके मृत भाई की पत्नी, लवलीना पुरबिया, के बीच एक लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवाद से उत्पन्न हुआ था. इस संबंध में, लवलीना द्वारा नीरज के खिलाफ पुलिस स्टेशन सुखेर में प्राथमिकी संख्या 91/2022 दर्ज की गई थी, जिसे बाद में निपटाया गया, जिसके परिणामस्वरूप अदालत में एक अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. इन कार्यवाहियों के दौरान, नीरज पुरबिया ने एसीबी मुख्यालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिससे एसीबी मामला संख्या 507/2022 दर्ज हुआ. बाद की जांच में शुरू में कुछ अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए गए थे; हालाँकि, जांच अभिकरण द्वारा गवाहों के बयानों, दस्तावेजी साक्ष्यों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आगे की जांच ने यह निर्धारित किया कि लवलीना पुरबिया, निखिल पोरवाल, राजेश कोठारी और अन्य के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है.

5. एक सावधानीपूर्वक और विस्तृत जांच पर, जिसमें आपराधिक विविध याचिका संख्या 1731/2024 में दर्ज किए गए अनुसार उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा एक व्यापक पुनरवलोकन शामिल है, यह न्यायालय जांच प्रक्रिया को पूरी तरह से और आश्वस्त करने वाला पाता है. इसके अलावा, महानिदेशक के साथ उचित विचार-विमर्श के बाद, अब इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन संतोषजनक प्रतीत होता है. संपूर्ण साक्ष्य सामग्री की कठोर जाँच, जिसमें प्रतिलेखों का सत्यापन, कॉल डिटेल् रिकॉर्ड (सीडीआर) का विश्लेषण, और स्वतंत्र साक्ष्य का आकलन शामिल है, ने इस निष्कर्ष पर पहुंचाया है कि संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कोई अपराध स्थापित नहीं होता है. समापन प्रतिवेदन, जिसे इस न्यायालय के समक्ष विधिवत प्रस्तुत किया गया है, को रिकॉर्ड पर लिया जाता है. यह देखते हुए कि आरोप अपुष्ट पाए गए, और एक नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन दायर किया जाना है, आगे विचार-विमर्श की कोई आवश्यकता नहीं है.
6. सावधानी के तौर पर, यह निर्देश दिया जाता है कि चूंकि जांच अभिकरण ने, एक पूर्ण जांच करने के बाद, याचिकाकर्ताओं को दोषी नहीं पाया है, इसलिए इस

संबंध में परीक्षण न्यायालय के एक विशिष्ट आदेश के बिना किसी भी बाद के चरण में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक उपाय नहीं किया जाएगा. तीनों याचिकाकर्ताओं से संबंधित समापन प्रतिवेदन इस आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी. परीक्षण न्यायालय, यदि आवश्यक हो, तो संलग्न सामग्री के साथ पूरक प्रतिवेदन पर विचार कर सकता है और इसे न्यायिक अभिलेख का हिस्सा बना सकता है.

7. उपरोक्त के मद्देनजर, ये तात्कालिक याचिकाएं अंततः निपटाई जाती हैं.

8. स्थगन याचिका का निपटारा किया जाता है.

आपराधिक विविध याचिका संख्या 3387/2023 (जितेंद्र), 905/2024 (मनोज श्रीमाली)

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत ये तात्कालिक याचिकाएं दायर करके, याचिकाकर्ता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 7 ए और 12, और भारतीय दंड संहिता की धारा 384 और 120 बी के तहत कथित अपराधों के लिए 30.12.2022 को पुलिस स्टेशन सीपीएस एसीबी चौकी, जयपुर में दर्ज प्राथमिकी संख्या 507/2022, साथ ही आरोप पत्र संख्या 83/2023 दिनांक 06.04.2023 को रद्द करने की मांग करते हैं, जिसमें याचिकाकर्ताओं को फंसाया गया है.
2. विवाद शिकायतकर्ता, नीरज पुरबिया, और उसके मृत भाई की पत्नी, लवलीना पुरबिया, के बीच एक संपत्ति को लेकर है. इस विवाद के कारण, लवलीना पुरबिया ने 18.02.2022 को पुलिस स्टेशन सुखेर में प्राथमिकी संख्या 91/2022 दर्ज की, जिसे अंततः समझौते के माध्यम से बंद कर दिया गया और 16.11.2022 को अदालत में एक अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. बाद में, शिकायतकर्ता ने 07.11.2022 को एसीबी मुख्यालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप 30.12.2022 को निरीक्षक रोशनलाल के खिलाफ एसीबी मामला संख्या 507/2022 दर्ज किया गया. जांच के बाद, निरीक्षक रोशनलाल, पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र कुमार आंचलिया, और निजी व्यक्तियों मनोज श्रीमाली और रमेश राठौर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड

संहिता की धारा 384 और 120 बी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई. हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के कारण लवलीना पुरबिया और अन्य के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच लंबित रखी गई थी. बाद की जांच में जितेंद्र कुमार आंचलिया, मनोज श्रीमाली, रमेश राठौर या अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कोई आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं मिला. इसमें शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास और जबरदस्ती या रिश्वतखोरी स्थापित करने के लिए स्वतंत्र साक्ष्य की कमी पर भी प्रकाश डाला गया. शिकायतकर्ता के आरोप अविश्वसनीय माने गए, और यह देखा गया कि विवाद मुख्य रूप से एक पारिवारिक संपत्ति मामले से उत्पन्न हुआ था. प्रकरण पत्रावली और साक्ष्य निष्कर्षों ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोपों का समर्थन नहीं किया, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि वे किसी भी आपराधिक कृत्य में शामिल नहीं थे.

3. पक्षकारों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की जाँच की गई.
4. न्यायालय ने इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा की गई संपूर्ण जांच प्रक्षेपवक्र की सावधानीपूर्वक जाँच की है, जिसमें प्राथमिक आरोप पत्र और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत प्रस्तुत किए गए बाद के जांच प्रतिवेदन शामिल हैं. यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत एक जांच के अनुसरण में दायर एक पूरक प्रतिवेदन एक स्वतंत्र दस्तावेज नहीं है, बल्कि मूल आरोप पत्र का एक विस्तार माना जाता है.
5. पूरक प्रतिवेदन और अंतिम जांच निष्कर्ष निर्णायक रूप से स्थापित करते हैं कि जांच की शुरुआत से लेकर समापन तक, सभी भौतिक साक्ष्यों की ईमानदारी से छानबीन की गई थी. तथ्यात्मक मैट्रिक्स का एक गहन आकलन स्पष्ट रूप से बताता है कि न तो अवैध परितोषण की मांग थी और न ही स्वीकृति या उसके प्रयास का कोई कार्य. इसके अलावा, प्रासंगिक समय पर, जितेंद्र कुमार आंचलिया के समक्ष कोई आधिकारिक कार्य लंबित नहीं था जो अवैध परितोषण की मांग को जन्म दे सकता था. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए अत्यावश्यक शर्त रिश्वत की प्रदर्शनकारी मांग और स्वीकृति है,

चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो. हालाँकि, जांच सामग्री, जब अत्यंत ध्यानपूर्वक और कानूनी छानबीन के साथ जाँच की गई, तो याचिकाकर्ताओं की ओर से ऐसी कोई दोषक्षमता इंगित नहीं करती है.

6. कुछ मामलों में लोक सेवकों के लिए यह असामान्य नहीं है कि वे शिकायतकर्ताओं या गवाहों को सीधे रिश्तत मांगने के बजाय तीसरे पक्ष के साथ संपर्क करने का निर्देश दें. हालाँकि, वर्तमान मामला ऐसी श्रेणी में नहीं आता है. रोशनलाल के कॉल डेटा रिकॉर्ड की सूक्ष्मता से जाँच की गई, और कहीं भी वे किसी संचार को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं जो यह आश्वासन दे रहा हो कि वह किसी भी अवैध मांग या व्यवस्था की सुविधा के लिए 'अपने वरिष्ठ से बात करेगा'. लोक सेवक पर आपराधिक दायित्व थोपने से पहले कम से कम ऐसा पुष्टि करने वाला साक्ष्य आवश्यक है. किसी लोक सेवक के करियर और स्वतंत्रता को खतरे में डालने का आधार किसी व्यक्ति के केवल मौखिक दावे नहीं हो सकते, जिन्हें स्वतंत्र, निर्विवाद साक्ष्य का समर्थन प्राप्त न हो। अस्पष्ट, अप्रमाणित और असत्यापित आरोपों के बल पर किसी लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा शुरू करना या जारी रखना अभियोजन नहीं, बल्कि उत्पीड़न होगा, जिसे आपराधिक न्याय प्रणाली बर्दाश्त नहीं कर सकती।
7. शुरू में, आरोपों के प्रथम दृष्टया मूल्यांकन पर, यह प्रतीत हुआ कि याचिकाकर्ता, एक वृत्ताधिकारी होने के नाते, का आचरण कुछ हद तक संदिग्ध था। हालाँकि, रिकॉर्ड की गहन जांच करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके कार्य वैधानिक रूप से परिभाषित 'दुराचार' की सीमाओं के भीतर नहीं आते हैं। यह धारणा कि उसने एक निजी विवाद में कोई भूमिका निभाई या हस्तक्षेप किया, स्वयं ही उसके आचरण को अवैध या गैरकानूनी नहीं बनाती है।
8. इस न्यायालय ने महानिदेशक (डीजी) से याचिकाकर्ता की आधिकारिक भूमिका और आचरण के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा। महानिदेशक ने राय दी कि एक वृत्ताधिकारी के रूप में अपनी क्षमता में, यदि उसने किसी भी समय पारिवारिक विवाद में मध्यस्थता करने की मांग की, तो ऐसे कार्य को अवैध या उसके सौंपे गए कर्तव्यों के दायरे से बाहर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अपने अधिकार क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना उसके आधिकारिक अधिदेश के

दायरे में आता है।

9. प्रारंभिक जांच अधिकारी ने एक सीमित आकलन के आधार पर, कथित अपराधों के होने का निष्कर्ष निकाला और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए आगे बढ़ा। हालाँकि, जांच अधूरा रही। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच करने का जांच अभिकरण का अधिकार अपरिवर्तनीय है और कानूनी जांच प्रक्रिया की सीमाओं के भीतर है। अभिकरण के पास अतिरिक्त सामग्री एकत्र करने और एक पूरक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का वैध विशेषाधिकार है, जिसका वर्तमान मामले में विधिवत प्रयोग किया गया था। ऐसी कार्रवाई के लिए कोई कानूनी बाधा मौजूद नहीं है।
10. अभिकरण ने, पहले और दूसरे दोनों जांच अधिकारियों के प्रतिवेदनों का विश्लेषण करने के बाद, पाया है कि उनमें विरोधाभासी निष्कर्षों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता, नीरज पुरबिया, ने बिना किसी उचित कारण के नौ महीने तक एसीबी मुख्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करने में देरी की, न ही उसने इस अवधि के दौरान किसी अन्य प्राधिकरण से संपर्क किया। इसके अतिरिक्त, जून 2022 तक, जितेंद्र कुमार आंचलिया का पहले ही वृत्ताधिकारी के पद से स्थानांतरण हो चुका था, और शिकायतकर्ता से संबंधित कोई आधिकारिक कार्य उसके समक्ष लंबित नहीं था। विचाराधीन संपत्ति विवाद, जो उसकी उपस्थिति में सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया था, में न तो उसके और न ही किसी अन्य अभियुक्त से कोई जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव शामिल था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत शिकायतकर्ता के बयानों में कथित रिश्वत की मांग के संबंध में विसंगतियाँ हैं, और आंचलिया या अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों को, कोई पुष्टि करने वाला साक्ष्य—चाहे वह मौखिक, दस्तावेजी या तकनीकी हो—पुष्टि नहीं करता है। यहाँ तक कि कॉल डेटा रिकॉर्ड और रिकॉर्ड किए गए वार्तालाप भी अवैध परितोषण की किसी मांग या स्वीकृति को इंगित करने में विफल रहते हैं। ये महत्वपूर्ण पहलू इस निष्कर्ष को और मजबूत करते हैं कि आरोपों में आवश्यक साक्ष्य आधार की कमी है।
11. आगे बढ़ने से पहले, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत पूरक प्रतिवेदनों को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों की जांच करना अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विनय त्यागी बनाम इरशाद अली @**

दीपक और अन्य, (13 दिसंबर 2012 को निर्णीत) के मामले में, नई जांच, पुनः जांच, नए सिरे से जांच और ऐसे परिदृश्यों में न्यायालय और मजिस्ट्रेट की शक्तियों की अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा की है। उत्पन्न होने वाला प्रासंगिक मुद्दा पूरक प्रतिवेदन की कानूनी स्थिति है जब यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के तहत दायर प्राथमिक आरोप पत्र में दर्ज निष्कर्षों, टिप्पणियों और विचारों को अस्वीकार करती है। इसलिए, प्रश्न यह है कि क्या एक पूरक आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर प्राथमिक आरोप पत्र को अधिभावी कर सकता है या उसे अप्रभावी बना सकता है। उत्तर अस्पष्ट रूप से नकारात्मक है। एक बार जब एक जांच प्रतिवेदन कानून के अनुसार सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है, तो जांच अभिकरण के पास पिछले प्रतिवेदन को एकतरफा रह या शून्य करने का अधिकार नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में, दो विपरीत जांच प्रतिवेदन मौजूद होते हैं। ऐसे प्रतिवेदनों से निपटने में न्यायालय द्वारा अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण न्यायिक विवेक का मामला नहीं, बल्कि एक कानूनी आवश्यकता है। यदि बाद का प्रतिवेदन भी न्यायालय के समक्ष रखा जाता है और आरोप तय करने का मुद्दा अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, तो परीक्षण न्यायालय को दोनों प्रतिवेदनों का सावधानीपूर्वक आकलन करना आवश्यक है। न्यायालय को तब यह तय करना होगा कि क्या अभियुक्त के दोष का अनुमान लगाने के लिए उचित आधार मौजूद हैं, जिसके लिए परीक्षण की आवश्यकता है, या क्या अभियुक्त को उन्मोचित किया जाना चाहिए। इस कानूनी स्थिति पर उपरोक्त उद्धृत निर्णय में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इन मुद्दों को संबोधित करने वाले प्रासंगिक अनुच्छेद यहाँ नीचे दिए गए हैं:

“31. संहिता की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति के दायरे पर चर्चा करने के बाद, अब हमें उन प्रकार के प्रतिवेदनों की जांच करनी होगी जिनकी संहिता के प्रावधानों और/या इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसार परिकल्पना की गई है। मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार तक पहुंचने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रथम सूचना रिपोर्ट है। फिर, जांच पूरी होने पर, पुलिस को संहिता की धारा 173(2) के संदर्भ में एक प्रतिवेदन दाखिल करना होता है। इस प्रतिवेदन को प्राथमिक रिपोर्ट कहना उचित होगा, क्योंकि यह न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के मामले की नींव है। यह मामले का अभिलेख और उससे संलग्न दस्तावेज हैं, जिन पर न्यायालय विचार करता है और फिर मजिस्ट्रेट के न्यायालय से उपरोक्त तीन विकल्पों

में से किसी एक का प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है। न्यायालय के पास बताए गए विकल्पों में से, वह जिस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा, उसे कानून के स्थापित सिद्धांतों के सख्त अनुरूप होना चाहिए। 'आगे की जांच' का निर्देश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति एक महत्वपूर्ण शक्ति है जिसका प्रयोग कम ही, असाधारण मामलों में और न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। निष्पक्ष, उचित और निर्विवाद जांच प्रदान करना जांच अभिकरण का दायित्व है और न्यायालय को अपनी पर्यवेक्षी क्षमता में इसे सुनिश्चित करना आवश्यक है। न्यायालय के आदेशों के तहत की गई आगे की जांच, जिसमें मजिस्ट्रेट का आदेश या पुलिस द्वारा अपने स्वयं के समझौते पर और वैध कारणों से की गई जांच शामिल है, एक पूरक रिपोर्ट दाखिल करने की ओर ले जाएगी। ऐसी पूरक रिपोर्ट को प्राथमिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में माना जाएगा। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि संहिता की धारा 173(8) के संदर्भ में संहिता की धारा 173(3) से 173(6) के प्रावधान ऐसी रिपोर्टों पर लागू होंगे।

32. इन दोनों रिपोर्टों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना है और यह रिपोर्टें और उनसे संलग्न दस्तावेजों का संचयी प्रभाव है जिस पर न्यायालय से यह निर्धारित करने के लिए अपना ध्यान लगाने की अपेक्षा की जाएगी कि क्या यह अनुमान लगाने के लिए आधार मौजूद हैं कि अभियुक्त ने अपराध किया है। यदि इन रिपोर्टों के आधार पर उत्तर नकारात्मक है, तो न्यायालय संहिता की धारा 227 के प्रावधानों के अनुपालन में एक अभियुक्त को उन्मोचित करेगा।

33. इस स्तर पर, हम आपराधिक न्यायशास्त्र का एक और सुस्थापित सिद्धांत भी बता सकते हैं कि उच्च न्यायालयों के पास संहिता की धारा 482 के तहत या यहाँ तक कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत 'आगे की जांच', 'नई' या 'नए सिरे से' और यहाँ तक कि 'पुनः जांच' का निर्देश देने का क्षेत्राधिकार है। 'नई', 'नए सिरे से', और 'पुनः जांच' पर्यायवाची अभिव्यक्ति हैं और कानून में उनका परिणाम समान होगा। उच्च न्यायालयों को एक अभिकरण से दूसरे अभिकरण को जांच हस्तांतरित करने की शक्ति भी निहित है, बशर्ते कि न्याय के उद्देश्य ऐसे कार्रवाई की मांग करें। बेशक, यह भी एक स्थापित सिद्धांत है कि इस शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालयों द्वारा बहुत कम ही और अत्यंत सावधानी के साथ किया जाना है।

34. हमने इस मुद्दे पर कुछ विस्तार से विचार किया है कि संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ संहिता की धारा 228 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति की सीमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित या सीमित नहीं करती हैं। जहाँ भी न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, वहाँ भी यह न्यायालय आम तौर पर जांच को फिर से नहीं खोलेगा, खासकर इसे किसी विशिष्ट अभिकरण को सौंपकर। यह सुरक्षित रूप से

कहा और निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक उपयुक्त मामले में, जब न्यायालय को लगता है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच उचित दिशा में नहीं है और पूर्ण न्याय करने के लिए और जहाँ मामले के तथ्य मांग करते हैं, तो न्यायालय के लिए जांच को एक विशिष्ट अभिकरण को सौंपना, हमेशा खुला रहता है। इन सिद्धांतों को इस न्यायालय के निर्णयों में दिशा बनाम गुजरात राज्य और अन्य [(2011) 13 SCC 337], विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [(1998) 1 SCC 226], भारत संघ और अन्य बनाम सुशील कुमार मोदी और अन्य [1996 (6) SCC 500] और रुबाबुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य और अन्य [(2010) 2 SCC 200] के मामले में अनुमोदन के साथ दोहराया गया है।

35. 'पुनः जांच' या 'नए सिरे से' जांच का आदेश/निर्देश देने की शक्ति उच्च न्यायालयों के दायरे में आती है, वह भी असाधारण मामलों में। यदि कोई संहिता के प्रावधानों की जांच करता है, तो रिपोर्टों को रद्द करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, सिवाय इसके कि जांच अभिकरण एक समापन प्रतिवेदन दाखिल कर सकती है (जहाँ जांच अभिकरण के अनुसार, कोई अपराध नहीं बनता है)। यहाँ तक कि ऐसी रिपोर्ट भी विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किए जाने के अधीन है, जो अपने विवेक से ऐसी रिपोर्ट को स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी। वैध कारणों से, न्यायालय, ऐसी रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार करके, 'आगे की जांच' का निर्देश दे सकता है, या यहाँ तक कि मामले के अभिलेख और उससे संलग्न दस्तावेजों के आधार पर, अभियुक्त को तलब कर सकता है।

36. संहिता में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो, सक्षम न्यायालय द्वारा 'नई जांच' का निर्देश देने,, ऐसी जांच किन परिस्थितियों में आयोजित की जा सकती है, यदि बिल्कुल भी, और अंत में उस प्रतिवेदन से कैसे निपटा जाएगा, जिससे वह प्राप्त होती है, से संबंधित हो। उच्च न्यायालय 'नई/सिरे से' जांच आयोजित करने का निर्देश दे सकते हैं, लेकिन जब तक यह विशेष रूप से निर्देश नहीं देता है कि पहले से तैयार की गई रिपोर्ट या अब तक आयोजित की गई जांच मामले के अभिलेख का हिस्सा नहीं बनेगी, ऐसी रिपोर्ट को अभिलेख का हिस्सा माना जाएगा। एक बार जब यह अभिलेख का हिस्सा बन जाता है, तो विद्वान मजिस्ट्रेट के पास इसे मामले के अभिलेख से बाहर करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट आदेश के लिए, रिपोर्टें, चाहे वह एक प्राथमिक रिपोर्ट हो या 'आगे की जांच' पर एक रिपोर्ट या 'नई जांच' पर एक रिपोर्ट, को संयुक्त रूप से समझा और पढ़ा जाना होगा। जहाँ न्यायालय द्वारा विशिष्ट आदेश दिया गया है, जैसे कि जांच के पूरी तरह से अन्यायपूर्ण, दूषित, अवांछनीय होने या कोई सत्य नहीं होने जैसे कारणों से, न्यायालय को विशेष रूप से निर्देश देना होगा कि इस प्रकार आयोजित जांच या

कार्यवाही रद्द हो जाएगी और सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा विचार के लिए अभिलेख का हिस्सा नहीं बनेगी।

37. संहिता की धारा 173 की योजना न्यायालय को प्रस्तुत दस्तावेजों या बयानों का अपवर्जन करने की योजना से भी संबंधित है। इस संबंध में, कोई भी संहिता की धारा 173(6) के प्रावधानों का उल्लेख कर सकता है, जो जांच अभिकरण को न्यायालय से बयान या अभिलेख के उस हिस्से को अपवर्जित करने व अभियुक्त को उसकी प्रतियां प्रदान करने से अपवर्जित करने का अनुरोध करने का अधिकार देता है और , जो न्याय के हित में आवश्यक नहीं हैं, और जहाँ ऐसे बयान प्रस्तुत करना सार्वजनिक हित में असंगत होगा। कानून के निर्माताओं ने, अपने विवेक से, बहिष्करण का एक सीमित तरीका विशेष रूप से प्रदान किया है, जिसका मानदंड अभियुक्त का कोई अन्याय नहीं होना और अधिक सार्वजनिक हित प्रदान किया जाना है। यह स्वयं संबंधित अभिकरण द्वारा निष्पक्ष और उचित जांच की आवश्यकता को इंगित करता है। आपराधिक न्यायशास्त्र में 'निष्पक्ष और उचित जांच' अभिव्यक्ति का अंतिम लक्ष्य या महत्व क्या है? इसका दोहरा उद्देश्य है। सबसे पहले, जांच निष्पक्ष, ईमानदार, न्यायपूर्ण और कानून के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा, निष्पक्ष जांच पर पूरा जोर सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समक्ष मामले की सच्चाई को सामने लाना होना चाहिए। एक बार जब निष्पक्ष जांच के ये दोनों प्रतिमान संतुष्ट हो जाते हैं, तो कानून के न्यायालय के लिए जांच में हस्तक्षेप करने की सबसे कम आवश्यकता होगी, इसे रद्द करने या इसे किसी अन्य अभिकरण को हस्तांतरित करने की तो बात ही दूर है। निष्पक्ष और खोजी साधनों द्वारा कानून के अनुसार सच्चाई को सामने लाना अनिवार्य रूप से एक अनुचित, दूषित जांच या झूठे फंसाने के मामलों के बहुत आधार को दूर करेगा। इस प्रकार, कानून के न्यायालय के लिए जांच के भाग्य के बारे में एक विशिष्ट आदेश पारित करना अपरिहार्य है, जो उसकी राय में अनुचित, दूषित है और खोजी सिद्धांतों के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन है।

38. अब, हम एक और महत्वपूर्ण पहलू की जांच कर सकते हैं कि धारा 173(8) के प्रावधानों को न्यायालयों और जांच अभिकरणों द्वारा कैसे समझा और लागू किया गया है। यह सच है कि यद्यपि संहिता की धारा 173(8) के प्रावधानों में न्यायालय की अनुमति से 'आगे की जांच' करने या पूरक रिपोर्ट दाखिल करने की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियों ने न केवल इसे समझा है, बल्कि 'आगे की जांच' करने और न्यायालय की अनुमति से 'पूरक प्रतिवेदन' दाखिल करने के लिए न्यायालयों की अनुमति लेने को एक कानूनी अभ्यास के रूप में अपनाया है। कुछ निर्णयों में न्यायालयों ने भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है। 'आगे की जांच' करने और/या 'पूरक प्रतिवेदन' दाखिल करने के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता को संहिता की धारा 173(8) के प्रावधानों में पढ़ा जाना

होगा, और यह एक आवश्यक निहितार्थ है। समकालीन व्याख्या का सिद्धांत इस तरह की व्याख्या के लिए पूरी तरह से मदद करेगा क्योंकि जो मामले लंबे समय से समझे और लागू किए जाते हैं, और ऐसा अभ्यास जो कानून द्वारा समर्थित है, उसे व्याख्यात्मक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

39. इस तरह के दृश्य को दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से समर्थित किया जा सकता है। सबसे पहले, पूर्वाग्रह के सिद्धांत के माध्यम से, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, क्योंकि न्यायालयों ने अक्सर ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है, और, दूसरा, जांच अभिकरणों जिन्होंने सिद्धांत को समझा और लागू भी किया है। जो मामले कानूनी अभ्यास के रूप में समझे और क्रियान्वित किए जाते हैं और कानून के मूल नियम के विपरीत नहीं हैं, वे अच्छे अभ्यास होंगे और ऐसी व्याख्या समकालीन व्याख्या के सिद्धांत की मदद से अनुमेय होगी। अन्यथा भी, न्यायालय की ऐसी अनुमति लेना न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा और एक संदिग्ध/अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान करेगा।

40. हमने पहले ही उल्लेख किया है कि संहिता की धारा 173(2) के संदर्भ में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर 'आगे की जांच' का निर्देश देने की विद्वान मजिस्ट्रेट की शक्ति पर कोई विशिष्ट रोक नहीं है। कोई भी अन्य दृष्टिकोण या व्याख्या धारा 173(8) की भाषा और आपराधिक न्याय के उचित प्रशासन को प्राथमिकता देने के लिए संहिता की योजना के विपरीत होगी। आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांत ऐसे दृष्टिकोण का समर्थन करेंगे, विशेष रूप से जब संहिता की धारा 190 के संदर्भ में, मजिस्ट्रेट एक अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। यह मजिस्ट्रेट ही है जिसे यह तय करना होता है कि अभिलेख और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, कोई अपराध बनता है या नहीं, और यदि बनता है, तो सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय को मामले को सौंपने या स्वयं मुकदमे के साथ आगे बढ़ने के संबंध में कानून के किस मार्ग को अपनाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह मजिस्ट्रेट की न्यायिक अंतरात्मा है जिसे जांच अभिकरण द्वारा उसके समक्ष रखे गए अभिलेख और दस्तावेजों के संदर्भ में संतुष्ट होना है, ताकि कानून के सिद्धांतों के अनुरूप उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। यह न्याय का उपहास होगा, यदि न्यायालय को अपने संदेह को दूर करने और जांच अभिकरण को अपने आरोप पत्र को और पुष्ट करने का निर्देश देने के लिए 'आगे की जांच' का निर्देश देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समक्ष आगे की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक पूर्व शर्त है। मजिस्ट्रेट को 'आगे की जांच' का निर्देश देना चाहिए या नहीं, यह फिर से एक मामला है जो किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। विद्वान मजिस्ट्रेट या सक्षम क्षेत्राधिकार का उच्च न्यायालय किसी दिए गए मामले के

तथ्यों पर 'आगे की जांच' या 'पुनः जांच' का निर्देश देगा, जैसा भी मामला हो। जहाँ मजिस्ट्रेट केवल आगे की जांच का निर्देश दे सकता है, वहीं उच्च क्षेत्राधिकार के न्यायालय किसी दिए गए मामले के तथ्यों के आधार पर आगे, पुनः जांच या यहाँ तक कि सिरे से जांच का निर्देश दे सकते हैं। यह न्यायालय का विशिष्ट आदेश होगा जो जांच की प्रकृति को निर्धारित करेगा। इस संबंध में, हम सिवानमूर्ति और अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व राज्य [(2010) 12 SCC 29] के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं। उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम इस निर्णय के उद्घाटन में तैयार किए गए प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार देते हैं: सक्षम क्षेत्राधिकार का न्यायालय जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सभी प्रतिवेदनों, संपूर्ण अभिलेख और दस्तावेजों को संहिता की धारा 173(2) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट के रूप में मानने के लिए कर्तव्यबद्ध है। यह नियम केवल निम्नलिखित अपवादों के अधीन है; क) जहाँ अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा कोई भी दस्तावेज़ या बयान या उसके किसी भी हिस्से को बाहर करने के लिए सीमित एक विशिष्ट आदेश पारित किया गया है; ख) जहाँ उच्च न्यायालयों द्वारा अपने असाधारण या अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग में एक आदेश पारित किया जाता है, जिसमें निर्देश दिया जाता है कि कोई भी रिपोर्ट, यानी प्राथमिक रिपोर्ट, पूरक रिपोर्ट या 'नई जांच' या 'पुनः जांच' पर प्रस्तुत रिपोर्ट या उसका कोई भी हिस्सा बाहर रखा जाए, न्यायालय के अभिलेख से हटा दिया जाए और गैर-मौजूद माना जाए। कोई भी जांच अभिकरण उस अपराध के संबंध में 'नई', 'सिरे से' या 'पुनः जांच' आयोजित करने के लिए सशक्त नहीं है जिसके लिए उसने पहले ही संहिता की धारा 173(2) के संदर्भ में एक प्रतिवेदन दाखिल कर दिया है। यह केवल ऐसे आदेश पारित करने के लिए सशक्त उच्च न्यायालयों के आदेशों पर ही है कि उपरोक्त जांच आयोजित की जा सकती है, जिस स्थिति में उच्च न्यायालयों को पहले से आयोजित जांच के भाग्य और विद्वान मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष दायर की गई रिपोर्ट के संबंध में एक विशिष्ट आदेश पारित करना होगा।

41. कानून के प्रश्नों का उत्तर पूर्वोक्त रूप से देने के बाद, हम विचाराधीन मामले के तथ्यों पर वापस आते हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी कि प्राथमिकी संख्या 10/2006 दिनांक 9 फरवरी, 2006 की जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र जांच अभिकरण को हस्तांतरित की जाए, याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, त्रुटिपूर्ण पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया जाए जिन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है और ऐसे अन्य आदेश जो न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे। यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के साथ पठित संहिता की धारा 482

के तहत 25 फरवरी, 2006 को दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने अभिकरण द्वारा आगे की जांच पर रोक लगाने या सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं दिया। दिल्ली पुलिस ने स्वयं 4 अप्रैल, 2006 को उच्च न्यायालय के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट दायर की और दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने 6 मई, 2006 को परीक्षण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया। उच्च न्यायालय को प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट की जाँच करने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 9 मई, 2006 के आदेश द्वारा उल्लेख किया था कि मामले की परिस्थितियों ने अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा किया था, अभियुक्तों को किस तरह से पकड़ा गया और उनसे विस्फोटक और डेटोनेटर जैसी वस्तुओं की कथित बरामदगी की गई। इसका उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले के गुणों पर टिप्पणी किए बिना, उसकी राय थी कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें कुछ स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा पूछताछ की आवश्यकता थी, और सीबीआई को मामले में पूछताछ करने और चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जाहिर है, उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया होगा कि दिल्ली पुलिस ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की थी। स्थिति रिपोर्ट भी उच्च न्यायालय के समक्ष रखी गई थी। फिर भी, उच्च न्यायालय ने, अपने विवेक से, सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने वाले किसी भी निर्देश को पारित करना उचित नहीं समझा। उच्च न्यायालय के समक्ष एक पर्याप्त अवधि के लिए लंबित होने के बावजूद, सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक पूछताछ करने में काफी समय लिया और यह 4 जुलाई, 2007 को ही था कि सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक पूछताछ रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। रिपोर्ट की जाँच करने के बाद, न्यायालय ने, सीबीआई के अनुरोध के अनुसार, मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिया।

42. 24 अक्टूबर, 2007 के आदेश में, उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि इस तथ्य के बावजूद कि सीबीआई ने अपनी जांच पूरी करने में काफी समय लिया था, उसने अभी भी ऐसा नहीं किया था। यह देखते हुए कि जांच 9 मई, 2006 को सीबीआई को सौंप दी गई थी और विस्तार के बावजूद उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की थी, न्यायालय ने सीबीआई को आदेश की तारीख से चार सप्ताह का समय दिया कि वह शिकायत में अभियुक्त द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करे और मामले को 28 नवंबर, 2007 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। जिस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि न्यायालय ने इस आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया कि 'मामले का मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे उम्मीद है कि सीबीआई परीक्षण न्यायालय के समक्ष पूरक रिपोर्ट या पूरक सामग्री दाखिल करेगी और अभियुक्त को

औपचारिक रूप से जांच किए गए मामले का अवसर मिलता है। हालाँकि, जिस गति से सीबीआई द्वारा जांच की जाती है, वह दर्शाता है कि सीबीआई को अभिलेख प्राप्त करने में वर्षों लग सकते हैं...।'

43. यह आदेश स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उच्च न्यायालय ने एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की परिकल्पना की थी, जिसका अर्थ है दिल्ली पुलिस द्वारा संहिता की धारा 173(2) के तहत पहले से प्रस्तुत प्रतिवेदन की निरंतरता में प्रतिवेदन।

44. 28 नवंबर, 2007 को, मामला उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया। तब सीबीआई ने अपनी समापन रिपोर्ट दायर की जिसमें अनुरोध किया गया कि दोनों अभियुक्तों को उन्मोचित कर दिया जाए। मामला 4 अगस्त, 2008 को उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जब न्यायालय ने उल्लेख किया कि सीबीआई ने एक मोहरबंद लिफाफे में एक प्रतिवेदन दायर किया था और न्यायालय ने इसकी जांच की थी। यहाँ, न्यायालय ने पूरे तथ्यों को बहुत विस्तार से उल्लेख किया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा किया और पहले के आदेश दिनांक 4 जुलाई, 2007 का उल्लेख करते हुए, जिसमें अभियुक्त व्यक्तियों ने न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वे सीबीआई जांच पूरी होने तक परीक्षण न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन नहीं करेंगे, आवेदकों को जमानत आवेदन करने की भी अनुमति दी।

45. सीबीआई द्वारा दायर समापन रिपोर्ट के बल पर अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दायर उन्मोचन के आवेदन को परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 13 फरवरी, 2009 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, इस आधार पर कि उसे दिल्ली पुलिस द्वारा संहिता की धारा 173(2) के तहत दायर प्रतिवेदन सहित पूरे अभिलेख की जांच करनी थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि यह केवल सीबीआई द्वारा दायर समापन रिपोर्ट ही थी जिसे विचार में लिया जा सकता है, और तब मामला कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। इस तरह, रिट याचिका का अंततः निपटारा कर दिया गया, जिसमें पार्टियों को 14 सितंबर, 2009 को परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया। उच्च न्यायालय ने के. चंद्रशेखर बनाम केरल राज्य और अन्य (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया कि एक बार जब जांच सीबीआई को हस्तांतरित हो जाती है, तो यह केवल वही अभिकरण है जिसे जांच के साथ आगे बढ़ना होगा न कि दिल्ली पुलिस की विशेष सेल।

46. हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अनुमोदन देने में असमर्थ हैं। के. चंद्रशेखर (उपरोक्त) के मामले में निर्णय, सबसे पहले कानून के किसी सिद्धांत को नहीं बताता है। यह उस मामले के विचित्र तथ्यों पर एक निर्णय है। दूसरा, यह वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है। उस मामले में, जब जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने का आदेश दिया

गया था तब पुलिस द्वारा जांच लंबित थी। वहाँ न्यायालय ने निर्देश दिया था कि आगे की जांच सीबीआई द्वारा जारी रखी जानी थी न कि दिल्ली पुलिस की विशेष सेल द्वारा।

47. वर्तमान मामले में, दिल्ली पुलिस की विशेष सेल द्वारा धारा 173(2) के संदर्भ में प्रतिवेदन पहले ही दायर किया जा चुका था, इससे पहले कि जांच सीबीआई को प्रारंभिक पूछताछ करने के लिए सौंपी गई थी। इसके अलावा, सीबीआई द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अंतिम जांच भी उस चरण में सीबीआई को नहीं सौंपी गई थी।

48. एक बार जब संहिता की धारा 173(2) के तहत एक प्रतिवेदन दायर किया जाता है, तो इसे केवल सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा ही रद्द, आगे बढ़ाया या मामला बंद किया जा सकता है, और वह भी कानून के अनुसार। न तो पुलिस और न ही एक विशिष्ट जांच अभिकरण को उक्त रिपोर्ट को रद्द करने का कोई अधिकार है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस द्वारा आगे की जांच पर या सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई आदेश या निर्देश पारित नहीं किया था।

49. इसके विपरीत, न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि यह पूरक या आगे की जांच और एक 'पूरक रिपोर्ट' दाखिल करने का मामला था।

50. एक बार जब न्यायालय ने यह दृष्टिकोण ले लिया है, तो पहली रिपोर्ट को वापस लिया गया, रद्द किया गया या निहितार्थ द्वारा अभिलेख से बाहर किए जाने योग्य मानने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वास्तव में, ऐसे आदेश देने के लिए सक्षम उच्च न्यायालय के एक विशिष्ट आदेश को छोड़कर, पिछली और साथ ही पूरक प्रतिवेदन अभिलेख का हिस्सा होंगी जिस पर परीक्षण न्यायालय से कानून के अनुसार किसी भी उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार करने की अपेक्षा की जाती है। यह नोट करना भी दिलचस्प है कि सीबीआई ने स्वयं न्यायालय के आदेश को समझा और केवल 'आगे की जांच' की जैसा कि 28 नवंबर, 2007 को उच्च न्यायालय के समक्ष सीबीआई द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट से स्पष्ट है।

51. हमारे विचार में, परीक्षण न्यायालय को पूरे अभिलेख पर विचार करना होगा, जिसमें संहिता की धारा 173(2) के तहत दायर दिल्ली पुलिस रिपोर्ट और साथ ही सीबीआई द्वारा दायर समा-पन रिपोर्ट और इन रिपोर्टों के साथ दायर दस्तावेज शामिल हैं।

52. ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षण न्यायालय के पास तीन विकल्प हो सकते हैं, सबसे पहले, वह उन्मोचन के लिए अभियुक्त के आवेदन को स्वीकार कर सकता है। दूसरा, वह निर्देश दे सकता है कि कानून के अनुसार मुकदमा आगे बढ़ाया जाए और तीसरा, यदि वह पहले से आयोजित जांच के किसी भी महत्वपूर्ण पहलू पर असंतुष्ट है और उसकी

विचारित राय में, न्याय के हित में 'आगे की जांच' का निर्देश देना उचित, उचित और आवश्यक है, तो वह ऐसा कर सकता है।"

12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत दायर एक पूरक रिपोर्ट प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग बनती है, और उन्मोचन के प्रश्न पर विचार करते समय परीक्षण न्यायालय द्वारा दोनों का समग्र रूप से आकलन किया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष को अभियुक्त को आपराधिक मुकदमे की कठिनाई के अधीन करने से पहले एक कानूनी रूप से टिकाऊ मामला प्रस्तुत करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्यवाही उत्पीड़न या प्रक्रिया के दुरुपयोग के एक साधन में पतित न हो।
13. जब आरोप तय करने पर सुनवाई होती है, तो आरोप को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत अनिवार्य करते हैं कि एक न्यायाधीश अभियोजन पक्ष के दावों के लिए मात्र साधन नहीं है, बल्कि न्यायिक विवेक का प्रयोग करके यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य कार्यवाही जारी रखने की वारंटी देने वाला एक मजबूत संदेह पैदा करते हैं। याचिकाकर्ताओं की दोषक्षमता की ओर इशारा करने वाली ठोस सामग्री की अनुपस्थिति में, उन्हें मुकदमे की कठिनाइयों से गुजरने के लिए मजबूर करना आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत होगा। पर्याप्त और विश्वसनीय भौतिक साक्ष्य से रहित एक प्राथमिकी का मात्र दर्ज होना, एक अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने का आधार नहीं हो सकता है।
14. उपरोक्त के आलोक में, जबकि यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग प्राथमिकी संख्या 507/2022, जो 30.12.2022 को पुलिस स्टेशन सीपीएस एसीबी चौकी, जयपुर में दर्ज की गई थी, साथ ही आरोप पत्र संख्या 83/2023 दिनांक 06.04.2023 को रद्द करने से परहेज करता है, यह परीक्षण न्यायालय को निर्देश देता है कि वह न्यायिक विवेक का उचित प्रयोग करते हुए, प्रारंभिक और पूरक दोनों प्रतिवेदनों सहित जांच सामग्री की संपूर्णता का आकलन करे। परीक्षण न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि याचिकाकर्ताओं को तब तक मुकदमे के अधीन न किया जाए जब तक कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित न हो जाए, और आरोप तय करने या उन्मोचन का आदेश कानून के स्थापित सिद्धांतों के सख्त अनुरूप पारित किया जाएगा। परिणामस्वरूप, परीक्षण न्यायालय, आरोप तय करने पर

विचार करते समय या उन्मोचन पर विचार करते समय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 और 228 के तहत घोषित न्यायिक अधिदेश के अनुरूप, प्रारंभिक आरोप पत्र और बाद के जांच निष्कर्षों दोनों सहित अभिलेख पर रखी गई सामग्री की संपूर्णता की बारीकी से जांच करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

15. यहाँ ऊपर दर्ज की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए, इन याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को उचित चरण पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष सभी अनुमेय कानूनी और तथ्यात्मक तर्कों को उठाने की स्वतंत्रता दी जाती है। परीक्षण न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह अभिलेख पर मौजूद सामग्री और विषय वस्तु को नियंत्रित करने वाले न्यायिक मिसालों के आलोक में एक तर्कसंगत आदेश पारित करे। परीक्षण न्यायालय संलग्न सामग्री के साथ पूरक रिपोर्ट पर भी विचार करेगा और इसे अपने पास उपलब्ध अभिलेख के अलावा न्यायिक अभिलेख का हिस्सा बनाएगा।

16. स्थगन याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(फ़रज़न्द अली), न्यायाधीश

110-ममता/-

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़